Publications of Xavier Institute of Social Research

The list of our publication with a brief descrtiption of the books given below gives an idea of our academic engagement and intervention in the field of social sciences with a special focus on Bihar.

A. Bihar Subaltern Study Series

एक्स०आई०एस०आर० का मुख्य उद्देश्य बुद्धिजीवियों, शिक्षाविदों एवं सामाजिक कार्यकर्त्ताओं के बीच ऐसी वैचारिक बहस को जन्म देना है जिससे आलोचनात्मक दृष्टिकोण एवं विचारधारा से उत्पन्न चिंतनों एवं दर्शनों द्वारा वैकल्पिक चिंतन की खोज करते हुए सामाजिक जागृति की प्रक्रिया को गति दी जा सके। इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु हमने इस श्रृंखला का शोध-आधारित अध्ययन और प्रकाशन प्रारंभ किया था।

1. **थारू एक अनूठी जनजाति**, by Prakash Chandra Dubey, 2006, Xavier Institute of Social Research, Patna, pp 308+18, HB, Rs. 300/-, ISBN 978-81-907860-3-4

डा० प्रकाश चन्द्र दुबे से रचित "थारू एक अनूठी जनजाति" नामक पुस्तक में थारूओं की लोक संस्कृति को विस्तार से समझने प्रयास किया गया है। वर्तमान में देश में लगभग 6 लाख थारू जनजाति के लोग निवास करते हैं, जिनमें से 3 लाख बिहार और 3 लाख उत्तरांचल में हैं। थारूओं की बहुत बड़ी आबादी नेपाल की तराई में रहती है। यहाँ इनकी संख्या लगभग 25 लाख के आस-पास है। इस पुस्तक को 12 अध्यायों में सजाया गया है, जिसमें थारू जनजाति का परिचय, उत्पति, आकृति, आहार, धर्म, संस्कार, साहित्य, कला एवं कृषि कौशल सहित कई विषयों का समावेश किया गया है। पुस्तक में थारूओं की वर्तमान समस्याओं का सामाधान एवं उनकी विकास की संभावनाओं की तलाशने का प्रयास किया गया है। इनकी लोक संस्कृति की जीवंतता काबिले तारीफ है। चाहे वह जन्म संस्कार हो या विवाह का विधान। कर्मकाण्ड, त्योहार एवं धार्मिक रीति-रिवाज इस जनजाति का आधार हैं। हस्त कला एवं सांस्कृतिक कलाओं में थारू जनजाति अन्य जातियों की तुलना में काफी समृद्ध है।

जेवियर इंस्ट्टियूट ऑफ सोशल रिसर्च द्वारा समाज के उपेक्षित वर्गों के सम्बन्ध में किये जा रहे शोध कार्यों अन्य जाति-जनजातियों के सम्बन्ध में पुस्तक प्रकाशित करने की योजना है। "थारू एक अनूठी जनजाति" जेवियर इंस्ट्टियूट ऑफ सोशल रिसर्च के सबाल्र्टन स्टडी सीरीज़ की पहली पुस्तक है।

2. **हाशिए पर खड़े बिहार के निषाद**, by Jose Kalapura & Purushottam, 2008, Xavier Institute of Social Research, Patna & Daanish Books, New Delhi, pp 86+8, PB, Rs. 90/-, ISBN 81-89654-37-3

"हाशिए पर खड़े बिहार के निषाद" जेवियर इंस्ट्टियूट ऑफ सोशल रिसर्च के सबाल्र्टन स्टडी सीरीज़ की दूसरी पुस्तक है। निषाद प्राचीनतम जाति-समुदाय में से एक है। इस समुदाय के लोग जलीय कृषि तथा जल से जुड़े अन्य व्यवसाय में परंपरा से लगे हुए हैं। पिछले सौ वर्षों में जल से जुड़े व्यवसायों और इस समुदाय के स्वरूप, दोनों में भारी बदलाव आया है। आर्थिक जीवन से आए परिवतनों के साथ ही साथ सामाजिक समूहों की भूमिका भी इस कालखंड में तेजी से बदली है। परिवर्तन के दौरान इसके स्वरूप में आए बदलाव को समझने के प्रयास का ही परिणाम है प्रस्तुत परिचयात्मक अध्ययन।

प्रस्तुत अध्ययन आधुनिकीकरण की प्रक्रिया में बिहार के निषाद समुदाय के स्वरूप में आए बदलाव को समझने का एक परिचयात्मक प्रयास है। विभिन्न युगों में सामाज के राजनीतिक-आर्थिक स्वरूप में बदलाव के साथ-साथ निषाद समुदाय की सामाजिक अवस्थिति निरंतर बदलती रही।

आर्थिक-सामाजिक दशा के साथ ही साथ निषाद समुदाय की मानसिकता में आए परिवर्तनों को भी समझना भी अध्ययन का महत्वपूर्ण पक्ष रहा है।

प्रस्तुत अध्ययन बहुत विस्तृत नहीं, परिचयात्मक है। ऐतिहासिक, धार्मिक और नृवंशीय पृष्ठभूमि पर चर्चा अध्ययन का अंग है। यह मिथकीय सूचनाओं के संग्रहण मात्र तक सीमित नहीं। अध्ययन में प्रस्तुत ऐतिहासिक सूचनाएँ निषादों की सामाजिक अवस्थिति में प्राचीन काल में भी आए बदलाव की जानकारी देते हैं।

प्रस्तुत अध्ययन में निषादों के धार्मिक विश्वास पर भी चर्चा की गई है। अध्ययन के आरंभिक भाग में बिहार के निषाद समुदाय की आबादी के आँकड़ों पर चर्चा की गई है। निषाद समुदाय विभिन्न उपजातियों में बँटा हुआ है। हाल-हाल तक इन्हें अलग-अलग जातियों के रूप में देखने की प्रवृति रही है। आधुनिकीकरण की प्रक्रिया में निषाद समुदाय के अंदर आए बदलाव को समझने और रेखांकित करने में अध्ययन कितना वस्तुनिष्ठ रह पाया है यह तो समुदाय के चेतनशील लोग और पाठक ही बता पाएँगे।

[पुरूषोत्तम और जोस कलापुरा]

3. **दलित लोकगाथाओं में प्रतिरोध,** by Hasan Imam & Jose Kalapura, 2009, Xavier Institute of Social Research, Patna & Daanish Books, New Delhi, pp 184+20, HB, Rs. 325/-, ISBN 81-89654-67-5

"दलित लोकगाथाओं में प्रतिरोध" जेवियर इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल रिसर्च के सबाल्टर्न स्टडी सीरीज की तीसरी पुस्तक है। लोकगाथाओं मेहनतकशों के रोजमर्रे के अनुभवों एवं संघर्षों के बीच से जन्म लेते सपनों एवं आकांक्षाओं की कलात्मक अभिव्यक्ति है। अपने समय और काल की विसंगतियों से मुठभेड़ करती दलितों, शोषितों एवं वंचितों की ये संघर्ष-गाथाएँ वर्तमान की आलोचना एवं बेहतर दुनिया के निर्माण का आह्वान करती हैं। और इस आह्वान के आदर्श की जड़े शोषितों, दलितों एवं वंचितों की उन सामाजिक एवं ऐतिहासिक परिस्थितियों में निहित हैं, जिनमें यह वर्ग या समाज विकसित हुआ है। बिहार की दलित जातियों में प्रचलित लोकगाथाएँ उन्हीं परिस्थितियों की आलोचनात्मक व्याख्या प्रस्तुत करती हैं। सामाजिक उत्पीड़न, आर्थिक शोषण तथा राजनैतिक एवं धार्मिक अपवर्जन के खिलाफ दलितों के बीच उपजते प्रतिरोध की मुखर अभिव्यक्ति हैं ये लोकगाथाएँ।

इस पुस्तक में प्रतिरोध के उपरोक्त तत्वों को रेखांकित करते हुए, मौजूदा समय की शोषक एवं वर्चस्ववादी विचारधाराओं से मुकाबले में, इनकी वैचारिक उपयोगिता की तलाश की कोशिश की गई है। बिहार के दलितों, शोषितों एवं वंचितों की परंपरा एवं चेतना में बसने वाली इन संघर्ष गाथाओं को उनके आज के मुक्ति संघर्ष के लिए, एक अतिरिक्त वैचारिक खुराक के रूप में देखना, इस शोध आधारित पुस्तक का लक्ष्य है।

4. **बिहार के नट - जीने की बाजीगरी**, by Jose Kalapura & Purushottam, 2012, Xavier Institute of Social Research, Patna & Daanish Books, New Delhi, pp 174, PB, Rs. 175/-, ISBN 978-93-81144-09-1

नट समुदाय के लोग भारत के अनेक राज्यों में मौजूद हैं - पश्चिम में गुजरात और राजस्थान से लेकर पूरब में बिहार और बंगाल तक। पेशा और सामाजिक संगठन, दोंनों ही मामलों में नट प्राचीनतम परंपरा के वाहक समुदायों में से एक हैं। विश्व के विभिन्न हिस्सों से आए यात्रियों के यात्रा वृत्तांतों तथा प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक साहित्य में असंख्य स्थानों पर नटों की चर्चा आई है। औपनिवेशिक

काल में देश के विभिन्न हिस्सों में अपराधी जनजाति कानून की निरंकुशता को झेलने के क्रम में यह समुदाय एकजुट हुआ। अपराधी जनजाति कानून के प्रावधानों के तहत ढाए गए जुल्म का परिणाम हुआ कि सामाजिक स्तर पर यह हाशिए पर चला गया।

आज भी नटों की कोई एक बनी-बनाई छवि नहीं है। वर्चस्व की प्रवृत्ति रखने वाले तबके के लोगों में इनकी एक छवि है, तो वर्चस्व को अस्वीकार करने वालों के बीच दूसरी। एक की नजर में नट या या नेटुआ समुदाय दरअसल अनाचार और दुराचार में आकंठ डूबा हुआ है। वहीं दूसरे पक्ष या दबे-कुचलों की नजर में यह वर्चस्व को स्वीकार न करने वाले संस्कृतिकर्मियों का समुदाय है। इन्हीं दो छवियों के बीच नटों की जीवनधारा गतिमान रही है।

यह पुस्तक अनधिसूचित समुदायों में रुचि रखने वाले समाजकर्मियों और मानवविज्ञानियों के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होगी। " बिहार के नट - जीने की बाजीगरी" जेवियर इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल रिसर्च के सबाल्टर्न स्टडी सीरीज की चौथी पुस्तक है।

5. **लोकगाथा - परिवर्तन की सांस्कृतिक अभिव्यक्ति**, by Hasan Imam, 2014, Xavier Institute of Social Research, Patna, Indian Social Institute, New Delhi & Jagriti Publication, Patna, pp 199, PB, Rs. 225/- & HB, Rs. 600/-, ISBN 978-93-82371-96-0

"लोकगाथा - परिवर्तन की सांस्कृतिक अभिव्यक्ति" जेवियर इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल रिसर्च के सबाल्टर्न स्टडी सीरीज की पाँचवीं पुस्तक आपके सामने है। इस श्रृंखला की तीसरी पुस्तक 'दलित लोकगाथाओं में प्रतिरोध' की रचना हसन इमाम और मैंने मिलकर की थी। उस अध्ययन के बाद हसनजी ने लोकगाथाओं का और अध्ययन करने की इच्छा प्रकट की। वैसे सूबे में इस विषय पर गहराई से अध्ययन नहीं हुआ है। लोकगाथाएँ अक्सर अधीनस्थ दर्जे के लोग, हाशिए के बाहर खड़े समाज में दबे हुए वर्ग के लोगों के जीवन के वास्तविक हकीकत को रेखांकित करते हैं, अभिव्यक्त करते हैं। इन गाथाओं के जरिए कलाकार एवं श्रोतागण असंतुलित, असंगत सामाजिक संरचना को परिवर्तित करना चाहते हैं। लोक कलाकारों के कई मुद्दों का अध्ययन करने की जरूरत महसूस कर हसनजी ने एक शोध-अध्ययन का प्रस्ताव लाया जिसका मार्गदर्शन करने के लिए मैं सहमत हुआ क्योंकि खुद वे हैं एक सामाजिक सांस्कृतिक कार्यकर्त्ता। 25 वर्षों से आम आदमी के मुद्दों को, विशेषकर, अधीनस्थ दर्जों के लोगों के मुद्दों को जनता के सामने लाने में उनकी अथक प्रतिबद्धता रही है। इसलिए मुझे विश्वास था कि वे प्रस्तावित अध्ययन को विधिवत पूरा कर पाएँगे।

बड़ी संतुष्टि के साथ मैं कह सकता हूँ कि हसनजी ने इस अध्ययन से एक्स०आई०एस०आर० के बिहार सबाल्टर्न स्टडी शोध श्रृंखला को एक कदम और आगे बढ़ाया है। एक और मंजिल तक पहुँचाया है। आशा नहीं पूर्ण विश्वास है कि एक्स०आई०एस०आर० के जरिए इस श्रृंखला के और भी शोध अध्ययन होंगे।

[जोस कलापुरा]

6. **लोकगाथा और स्त्री मुक्ति का प्रश्न,** by Hasan Imam, 2016, Xavier Institute of Social Research, Patna & Youth, Art Culture Department, Patna, pp 94+10+2, HB, Contribution, ISBN 978-81-907860-4-1

स्त्री मुक्ति का विमर्श समकालीन सामाजिक-सांस्कृतिक और आर्थिक-राजनीतिक विमर्श के केन्द्र में है। यह विमर्श एक ओर धार्मिक तत्ववादियों के वैचारिक और भौतिक हमलों से दो चार है

तो दूसरी तरफ साम्राज्यवादी वैश्वीकरण की गोख से जनमे 'पहचान की राजनीति' का शिकार भी हो रहा है।

यह शोधपुस्तक समकालीन स्त्री विमर्श के विभिन्न आयामों को रेखांकित करते हुए लोक सांस्कृतिक अभिव्यक्तियों, खासकर बिहार के लोकगाथाओं में दर्ज स्त्री मुक्ति के विभिन्न पहलूओं को समेटता है।

'लोक' द्वारा स्त्रियों के संदर्भ में संस्थागत धर्म, सामंती पितृसत्ता और पूँजीवादी उपभोक्तावाद के दमनकारी और अमानवीय विचारों की सांस्कृतिक-ऐतिहासिक आलोचना और स्त्रियों के लिए न्यायपूर्ण स्पेश की वकालत इस शोधपुस्तक का तत्व है। "लोकगाथा और स्त्री मुक्ति का प्रश्न" जेवियर इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल रिसर्च के सबाल्टर्न स्टडी सीरीज की छठी पुस्तक है।

7. **थारू जनजातियों की प्रकृति प्रसूत संस्कृति,** by Jose Kalapura & Praveen Kumar Madhu, 2016, Xavier Institute of Social Research, Patna & Youth, Art Culture Department, Patna, pp 86+10, HB, Contribution, ISBN 978-81-907860-5-8

"थारू जनजातियों की प्रकृति प्रसूत संस्कृति" जेवियर इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल रिसर्च के सबाल्टर्न स्टडी सीरीज की सातवीं पुस्तक है। थारू जनजाति नेपाल की तराई एवं भारत के नेपाल से सटे उत्तराखंड, उत्तर-प्रदेश एवं बिहार के सीमांचल क्षेत्रों में निवास करती है। इस पुस्तक में बिहार राज्य के पश्चिम चम्पारण जिले में निवास करने वाले थारू जनजातियों की अनोखी संस्कृति को चित्रित किया गया है। थारू जनजाति प्रकृति पर आधारित सरल सलीकेदार जीवन शैली एवं समृद्ध संस्कृति के लिए पहचानी जाती है। थारूओं का इतिहास प्राचीन है। उनकी जीवन-शैली एवं रहन-सहन अन्य लोगों को अपनी ओर कमोवेश आकर्षित करती है।

थारूओं के जीवन के विभिन्न पहलुओं को समझने और जानने के लिए उनके जीवन एवं संस्कृति से संबंधित जानकारियों को इस पुस्तक के सात अध्यायों में प्रस्तुत किया गया है। पुस्तक में उनके जीवन शैली, सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, आर्थिक एवं हस्तशिल्प से संबंधित पहलुओं का उल्लेख किया गया है। वर्तमान परिवेश में थारूओं के जीवन पर आधुनिकीकरण एवं तकनीकीकरण के परिणाम स्वरूप थारूओं की संस्कृति पर प्रभाव पड़ा है। थारू संस्कृति में हो रहे इन बदलाओं की वजह से थारू भी चिंतित हैं। उपसंहार में इसी परिवर्तन के संबंध में संक्षिप्त चर्चा की गई है। थारूओं के विकास के साथ उनकी संस्कृति को सुरक्षित रखने के लिए सरकारी एवं गैरसरकारी स्तर पर पहल की आवश्यकताओं को सुझाव के रूप में प्रस्तुत किया गया है। हस्तशिल्प कलाओं में उनकी निपुणता को दर्शाने के लिए चित्रों को भी इस पुस्तक में प्रस्तुत किया गया है। यह पुस्तक थारूओं के संस्कृति को समझने एवं जानने में पाठकों के लिए सहायक अवश्य होगा।

B. Human Rights Documentary Study Series

8. **बिहार में बाल मानवाधिकार 2000-2003**, Compiled & Edited by Dr. Jose Kalapura & Neeraj Kumar, 2006, Xavier Institute of Social Research, Patna, pp 136+14, PB, Rs. 150/-, ISBN 978-81-907860-0-3

जेवियर इंस्ट्टियूट ऑफ सोशल रिसर्च के मानवाधिकार डक्यूमेंटरी स्टडी सीरिज के प्रथम पुस्तक बिहार में बाल मानावाधिकार, 2000-03 में वर्ष 2000-03 के दौरान राज्य में बच्चों के अधिकारों से संबंधित अखबारों में छपे प्रमुख खबरों को शामिल किया गया है। मूल रूप से पुस्तक को

चार भागों में बांटा गया है। प्रथम भाग में राज्य में बच्चों के अधिकारों की वर्तमान स्थिति पर प्रकाश डाला गया है। दूसरे भाग में बच्चों के अधिकारों को दिन-रात होने वाले उल्लंघन की चर्चा की गयी है। पुस्तक के तृतीय भाग में सरकारी और गैर सरकारी तरीके से बच्चों के अधिकारों की रक्षा के लिए उठाये गये कदम का उल्लेख है और चौथे एवं अन्तिम भाग में उससे होने वाले परिणाम को रखा गया है। ध्यान रखने की बात यह है कि यह पुस्तक दैनिक समाचार पत्रों पर छपी रिपोर्टों का मात्र संकलन है जो बिहार के संदर्भ में पूरा ब्यौरा शायद नहीं देगा। मगर चुने हुये विषयों पर बहुत हद तक प्रकाश डालने में कामयाब होगा।

बाल मानवाधिकार हनन जैसे, बाल हिंसा, बाल वेश्यावृति के मामले आम लोगों की नजर से अछूते रह जाते हैं। वैसे तो प्रशासनिक अधिकारियों व पुलिस को ऐसी घटनाओं की कुछ हद तक औपचारिक जानकारी मिलती है लेकिन इस पुस्तक से उन्हें विस्तार से जानकारी मिलेगी। पुस्तक में साधारण सामाचारों से लेकर कई महत्वपूर्ण लेखों का उल्लेख है। साथ ही सरकार एवं स्वयंसेवी संगठनों द्वारा बच्चों के भविष्य संवारने के लिए उठाये जा रहे कदमों का भी उल्लेख कर पुस्तक के संकलनकर्त्ताओं ने समाज की नई दिशा दिखाने का प्रयास किया है।

आशा है कि बी०एस०आई० का बाल मानवाधिकार के विषय पर प्रकाशित डॉक्यूमेंटरी स्टडी सीरीज की यह पुस्तक न केवल आम पाठकों, समाज-शास्त्रियों व प्रशासनिक अधिकारियों का मार्गदर्शन करेगी बल्कि सामाजिक कार्यकर्त्ताओं की आवाज भी साबित होगी

[प्रस्तावना, कैलाश सत्यार्थी, संस्थापक - बचपन बचाओ आंदोलन]

9. **बिहार में महिला मानवाधिकार**, Compiled & Edited by Dr. Jose Kalapura & Neeraj Kumar, Xavier Institute of Social Research, Patna, pp 151+20, PB, Rs. 200/-, ISBN 978-81-907860-2-7

इस पुस्तक के माध्यम से 2000 से 2003 तक राज्य में महिला अधिकार से संबंधित घटी घटनाओं को पाठकों तक पहुंचाने का एक प्रयास है। राज्य की सभी घटनाओं के पुस्तक में सम्मिलित करना संभव नहीं था। अतः यहाँ राज्य प्रमुख खबरों को ही तरजीह दी है। साथ ही उन घटनाओं एवं समस्याओं के समाधान के संबंध में संगठनों की सोच को भी प्रमुखता से रखा गया है।

"पुस्तक में कई ऐसे घटनाओं का जिक्र है जो समाज के कमजोर एवं दलित व्यक्तियों के साथ घटी है। परन्तु प्रशासन और सरकार के नुमाइदों की नजर वहाँ तक नहीं पहुँच पाती है। इस पुस्तक के माध्यम से जेवियर इंस्टि्टयूट ऑफ सोशल रिसर्च ने जो बात समाज के समक्ष उठायी है वह काबिले तारिफ हैं इसका निश्चित रुप से सकारात्मक प्रभाव समाज पर पड़ेगा।

बिहार में महिला मानवाधिकार किताब की समीक्षा करने से यह पता चलता है कि राज्य की महिलाओं को अपना हक-अधिकार का उल्लंघन ही ज्यादा होता है और जो महिलायें अपनी खामोशी को तोड़कर अधिकार की बात करेंगी और न्याय के लिये प्रशासन का या न्यायालय का दरवाजा खटखटायेंगी तो उधर भी विविध पहलुओं को समझने के बदले, पुरुष प्रधान न्यायपालिका का भी प्रयास यह रहता है कि पीड़िता को चरित्रहीन साबित करना है। न्यायालय की लम्बी प्रक्रिया के चलते और संसाधन के अभाव से या परिवार-समाज के दवाब में आकर कई विहिता न्याय से वंचित होती हैं। यह बात याद रखना अति आवश्यक है कि 90% महिलायें जो अत्याचार का शिकार होती हैं वो दलित, गरीब महिलायें हैं। समाज का विडंबना है कि मासूम बच्ची से लेकर 60-65 साल की माताओं को भी पुरुष अपना हवश का शिकार बनाते हैं।

इस किताब के संपादको को मैं हार्दिक बधाईयाँ देती हूँ कि वे महिला मानवाधिकार से जुड़ी कई महत्वपूर्ण मुद्दा को एक साथ लाकर पाठकों और अध्ययनकत्ताओं के लिए एक पुस्तक तैयार किये

हैं। महिला मानवाधिकार की वर्त्तमान स्थिति और विविध आयामों का ठोस आंकड़े और उदाहरण इस किताब की विशेषता है। आशा करती हूँ कि यह किताब हर संघर्षशील महिला के हाथ में आयेगा ताकि वे अपना हक-अधिकार की लड़ाई की रणनीति आगे तय कर सके।"

[प्रस्तावना, सुधा वर्गीस, निर्देशिका, नारी गुंजन पटना]

10. **दलित मानवाधिकार व मीडिया**, Compiled & Edited by Dr. Jose Kalapura & Neeraj Kumar, 2008, Xavier Institute of Social Research, Patna, & Indian Social Institute, New Delhi, pp 178+28, PB, Rs. 200/-, ISBN 81-89762-25-4

दलित मानवाधिकार व मीडिया बिहार के दलितों की वर्त्तमान स्थिति पर आधारित पुस्तक है। बिहार के दलितों के समक्ष कई समस्याएँ हैं जिनका समाधान कर आगे बढ़ना है। दलितों को अपना रास्ता स्वयं तय करने की जरूरत है। दलित समाज को शिक्षा की रोशनी अपनी झोपड़ी तक पहुँचाने के लिए पहल करनी होगी। राज्य में बहुत बड़े दलित तबके के बच्चे बाल मजदूरी करने को विवश हैं। सरकार का प्रयास है कि इसपर लगाम लगे। राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर दलित समाज में अंधविश्वास कायम है। इससे उन्हें ऊपर उठने की जरूरत है।

जेवियर इंस्टिट्यूट ऑफ सोशल रिसर्च द्वारा दलित से सम्बन्धित पुस्तक के प्रकाशन से दलित समाज को नई दिशा मिलेगी तथा उनमें शक्ति का संचार होगा। इस पुस्तक में दलितों की जगह देने के लिए सार्थक पहल किया गया है जो एक सराहनीय प्रयास है।

लेखकों ने दलित समाज की गहरी वेदना को समझने की कोशिश में सफलता हासिल की है। जन चेतना को सही दिशा देने में यह पुस्तक मददगार साबित होगी। मुझे विश्वास है कि दलित जातियों की समस्याओं को समझने वाले लोगों के लिए यह पुस्तक उपयोगी सिद्ध होगी।

[प्रस्तावना, श्री उदय नारायण चौधरी, अध्यक्ष, बिहार विधान सभा, पटना]

11. **Dalit Rights in Bihar,** Compiled & Edited by Dr. Jose Kalapura & Prashant Ranjan Dutta, 2007, Xavier Institute of Social Research, Patna, pp 184+24, PB, Rs. 200/-, ISBN 978-81-907860-1-0

(From the Foreword) "I am happy to note that Dr. Jose Kalapura and Prashant Ranjan Datta of Bihar Social Institute, Patna, have compiled and edited paper clippings of renowned daily newspapers to bring out this book entitled, '***Dalit Rights in Bihar***'.

I have gone through this book. And I can say that they have done a great service to the deprived people of society. Such an important work requires immense courage, relentless effort, sincere dedication and team work.

This book, I am told, is the second one, the first one being on children in Hindi, titled, ***'Bihar Mein Baal Manwadhikar, 2000-03'***, in a series of six books of Bihar Social Institute's ***Human Rights Documentation Study Series***. The reports, documents, facts, and findings of this book, though focused on Bihar, are relevant to other states of the Indian Union as more or less the same conditions prevail there too.

The introductory part of this book is very comprehensive and sufficiently elaborate to understand the concept of Dalit rights, the location of Dalits in Bihar and their present economic, social and political status.

The book has been designed to include various aspects of human rights with respect to Dalits in Bihar. It contains five sections: 1) Dalit Situation, 2) Dalit Issues, 3) Violation of Dalit Human Rights, 4) Dalit Response and Movements, and 5) Initiatives for Protection of Human Rights. I need not go into details of these chapters.

The book throws light on certain consequences of deprivation of human rights. The birth of Naxalites or other extremist groups is, perhaps, the result of denial of human rights to the poor, especially Dalits. Exploitation by landlords and corruption of those in administration (Police &

Revenue) or the nexus of both these groups seem to have forced Dalits to organize themselves and fight against sexual exploitation and for land, minimum wages and human dignity.

I appreciate and congratulate 'Bihar Social Institute, Patna for this important book which will be welcomed by not only Dalits but also other castes, besides thinkers, research students and administrators."

Jiya Lal Arya, (Retd) Home Secretary, Government of Bihar

12. Children's Rights in Bihar: *A Documentary Study,* Complied & Edited by Dr. Jose Kalapura & Prashant Ranjan Dutta, 2008, Xavier Institute of Social Research, Patna, & Indian Social Institute, New Delhi, pp 314+31, PB, Rs. 200/-, ISBN 978-81-89762-24-7

(From the Foreword of the book) "I am happy that ***Children Rights in Bihar: A Documentary Study*** is being brought out for publication. Through its documented, researched data the compilers have attempted to bring out an overview of the state of Bihar's children with respect to human rights. Although the documents have been culled from newspaper reports, it presents somewhat a comprehensive picture of some important aspects of child rights such as legal provisions of child rights, extent of violation of child rights, initiatives taken by both Government and voluntary bodies, etc.

I congratulate the compilers of this book Dr. Jose Kalapura and Mr. Prashant Ranjan Dutt and the publishers Indian Social Institute of New Delhi and Xavier Institute of Social Research of Patna, for undertaking this painful task of documentation on child rights in Bihar. I am sure this will become a significant academic contribution. I hope that this work will be made use of by students, researchers, activists, civil administrators and other concerned citizens for pro-active action toward protection of child rights in Bihar."

Upendra Kumar Roy, Labour Commissioner, Government of Bihar

13. Women's Rights in Bihar: An Overview, Compiled & Edited by Dr. Jose Kalapura & Prashant Ranjan Dutta, 2008, Xavier Institute of Social Research, Patna, & Indian Social Institute, New Delhi, pp 293+28, PB, Rs. 200/-, ISBN 978-81-89762-23-0

(From the Foreword of the Book) "Woman's dignity is most vulnerable in caste and communal wars: women become the soft targets and are made to face physical and psychological violence. It is hard reality that in Bihar gender imbalance and injustice are much more prevalent than in other states. There is need to make an all out attempt to reorient our society and transform social ethos, educate people about the concept of women's dignity and the need to treat woman as human beings worthy of respect and dignity.

These are other related issues have been brought out in this documentary study entitled, ***Women's Rights in Bihar: An Overview.*** I am happy that such a documented, researched study is being published by the Indian Social Institute, New Delhi, in collaboration with Xavier Institute of Social Research of Patna. This study attempts to present an overview of the state of women's rights in Bihar from the reports and news clippings published in the daily newspapers. Presenting a thematic view of the subject, the book covers several related themes such as 1) Status of Women in Bihar, 2) Violation of Human Rights of Women, 3) Initiatives for Protection of Women's Rights, and 4) Women's Rights: Policies, Participation and Empowerment

I congratulate the compilers of this book--Dr. Jose Kalapura and Mr. Prashant Ranjan Dutt--for undertaking this painful task of documenting various aspects of women's rights in Bihar. As such this book which, I am told, is the sixth in the series of Human Rights Documentary Study of Xavier Institute of Social Research, will serve to fulfill the needs of students, researchers, activists, administrators and all others who are concerned about the rights of women."

- Sister Sabeena, Director, Bihar Mahila Samakhya Society, Patna.

C. Citizen's Rights Series

14. **बिहार में प्राथमिक शिक्षा - समस्याएँ एवं संभावनाएँ**, by Prakash Louis, 2005, Xavier Institute of Social Research, Patna, pp 53+6, PB, Rs. 30/-

शिक्षा क्षेत्र से जुड़े लोगों ने हमेशा यह माना है कि शिक्षा के मानव संसाधन के विकास से जोड़ा जाये। स्कूली शिक्षा सम्पूर्ण उच्च शिक्षा की आधारशिला है। इसमें भी प्रारंभिक स्तर की शिक्षा अत्यंत महत्वपूर्ण है। लेकिन हम यह भी जानते हैं कि बिहार में देश के अन्य राज्यों की तरह ही शिक्षा-व्यवस्था, प्रणाली, ढाँचा, पठन-पाठन सामग्री, शिक्षक आदि में अभूतपूर्व गिरावट आई है। और तो और सत्ताधारी और समाज के रखवालों ने तो शिक्षा जगत में भी राजनीति करना उचित समझा है परन्तु यहाँ की आम जनता और जागरूक नागरिक समूह ने चरमरा रही इस ढाँचे को जीवित रखा है। बिहार में "शिक्षा की भूख" जो व्यापक हो रही है, वइ इस बात का गवाह है कि अभिवंचित वर्ग में भी शिक्षा का प्रचार-प्रसार जोर पकड़ा है।

इन्हीं तथ्यों को पाठकों के सामने रखने के मकसद से यह पुस्तिका लिखी गई। साथ ही, बिहार को पिछड़ापन का पर्याय माननेवालों के सामने प्रदेश में हो रहे मंथन का जिक्र करना भी इस पुस्तिका का उद्देश्य है। जितने भी एजेंट शिक्षा जगत से जुड़े हैं, उनके बीच संवाद स्थापित कर विकल्पों को तलाशने की भी उम्मीद यह पुस्तिका दर्शाती है।

[प्रस्तावनाः प्रकाश लुईस]

15. **जनता कानून और अधिकार**, Compiled by Prakash Louis, 2006, Xavier Institute of Social Research, Patna, pp 99+5, PB, Rs. 50/-

इस पुस्तिका में भारत के वर्तमान सरकार की दो नीतियाँ प्रस्तुत की गई हैं। पहली राष्ट्रीय रोजगार गारंटी कानून 2005 । दूसरी, सूचना का अधिकार कानून 2005 । इन दोनों नीतियों को एक ही पुस्तिका में प्रस्तुत करने के पीछे मकसद यह है कि ये दोनों नीतियाँ वर्तमान समय में भारत सरकार द्वारा लागू की गई कई नीतियों में से महत्वपूर्ण नीतियाँ है। साथ ही, ये नीतियाँ गरीब-गुर्बा के जीवन से जुड़ी हुई हैं।

राष्ट्रीय रोजगार गारंटी कानून देश के गरीब तब के लोगों को अपनी निर्धनता का सामना करने के लिए मदद करेगा। सूचना का अधिकार कानून नागरिकों को सशक्त करता है कि वे अपने विषय में बनाए गए कानून, नीति, योजनाओं की जानकारी प्राप्त करें और विकास के नाम पर की गई खर्चा का ब्योरा लें। इस तरह वे सरकार को जिम्मेदार बना सकते हैं। वर्तमान समय में इन दोनों कानून की आवश्यकता है।

इस पुस्तिका में प्रस्तुत की गई सामग्री का क्रम एवं श्रोत इस प्रकार है। सबसे पहले हमने राष्ट्रीय रोजगार गारंटी कानून का परिचय दिया है। उसके बाद इस कानून का हिन्दी अनुवाद प्रस्तुत किया है। तीसरा क्रम में हमने इस कानून को समझने के लिए बनाई गई प्रवेशिका को रखा है। चौथा में हमने सूचना अधिकार कानून का परिचय पेश करने की कोशिश की है। पाँचवा में हमने इस कानून का हिन्दी अनुवाद पेश किया है। और अंत में इस कानून के मूलसार को प्रस्तुत किया है। इस आशा से यह किया गया है कि नागर समाज, स्वैच्छिक संस्थाए एवं आम आदमी को इन कानून के विभिन्न आयाम सरल रूप में उपलब्ध हो और वे इनका इस्तेमाल कर सकें।

[प्रस्तावनाः प्रकाश लुईस]

16. **बिहार पंचायत नवनिर्माण अभियान - प्रारंभिक दस्तावेज**, Compiled by Prakash Louis, 2006, Xavier Institute of Social Research, Patna, pp 99+5, PB, Rs. 50/-

"बिहार पंचायत नवनिर्माण अभियानः प्रारंभिक दस्तावेज" नामक यह पुस्तिका बिहार के पंचायती राज व्यवस्था को सशक्त करने के उद्देश्य से एक अभियान जो छिड़ा है, उसके संदर्भ में लिखी गई एक प्रारंभिक दस्तावेज है। पंचायतों के बारे में तथा बिहार पंचायतों के बारे में कई पुस्तकें लिखीं गई हैं इस पुस्तिका को लिखने के पीछे यही मकसद था कि अभियान के कई पहलुओं को न केवल अभियान से जुड़े व्यक्तियों एवं संस्थाओं के सामने रखें बल्कि आम जनता, राजनेता, सरकारी अफसर, नागर समाज एवं मीडिया के समक्ष रखें और बहस हो। इस उम्मीद से भी प्रेरित यह पुस्तिका लिखी गई है कि बहस से आगे बढ़कर बिहार के पंचायतों का सशक्तीकरण की दिशा में कोई कारगर काम हो।

बहरहाल बिहार पंचायत नवनिर्माण अभियान के सीमित उद्देश्य हैं आम जनता आनेवाली पंचायत चुनाव में अपना मत्ताधिकार का प्रयोग कर सके, लोक उम्मीदवारों पर बहस और उनका चयन हो, आम सहमति से दलित महिलाएं, अति पिछड़ी जाति और अल्पसंख्यक समुदायों से जन प्रतिनिधि चुने जाएं, ग्राम सभा का महत्व केन्द्र बिन्दु बनें, पंचायतों का सशक्तीकरण हो जिससे विकास और सुशासन की नींव मजबूत हो।

[प्रस्तावनाः प्रकाश लुईस]

17. **राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिकार - प्रावधान, क्रियान्वयन, उपलब्धियाँ, मुद्दे, समस्याएँ एवं संभावनाएँ**, Compiled by Prakash Louis, 2009, Xavier Institute of Social Research, Patna, pp 38+5, PB, Rs. 15/-

संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार ने अपने साझा न्यूनतम कार्यक्रम के मुताबिक राष्ट्रीय रोजगार गारंटी कानून 2005 को 2006 में लागू किया था। इसके पीछे उद्देश्य था, "रोजगार के अवसर पैदा किए जाए ताकि हरेक परिवार को सुरक्षित और अच्छे जीवनयापन का अवसर मिल सके।" इस कार्यक्रम को प्रारंभ किए 3 वर्ष पूरे होने को है। अब वक्त आ गया है कि इस कानून के क्रियान्वयन एवं प्रभाव का आकलन हो।

नरेगा के क्रियान्वयन में लगी ऐजेंसियाँ हो या इसका विश्लेषण करने वाले क्यों न हो अधिकतर इसके आंकड़ों को देखते हैं। एक प्रगतिशील कार्यक्रम जैसे नरेगा को उसकी व्यापकता में देखने की जरूरत है। जैसे कानूनी प्रावधान, योजना निर्देशन, क्रियान्वयन एवं प्रभाव। इस कार्यक्रम के तहत ग्रामीण जनता को रोजगार देना और सार्वजनिक संसाधनों का विकास करना उद्देश्य है। इस दिशा में जो भी प्रावधान है वह कहाँ तक लोगों तक पहुँचता है और लोग कितने हद तक इसका इस्तेमाल कर पाते हैं, यह मन्थन का विषय होना चाहिए। साथ ही, कितना ढाँचागत परिवर्तन लाने में यह सफल रहा है यह भी बुनियादी सवाल है।

18. **शिक्षा का अधिकार**, by Prakash Louis, 2011, Xavier Institute of Social Research, Patna, pp 146+6, PB, Rs. 50/-

"पढ़ने की जानकारी चलने-फिरने की क्षमता की तरह है। लिखने की जानकारी आरोहण करने की तरह है। हाथ, पैर, पंख आदि इंसान को उसके पहला और साधारण विद्यालय की किताबों की देन है।" लातीन अमेरिका की जोस मारी।

संविधान की धारा 46 में निर्दिष्ट है कि, "राज्य, जनता के दुर्बल वर्गों की विशिष्टतया अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की विशेष सावधानी से अभिवृद्धि करेगा और सामाजिक अन्याय और सभी प्रकार के शोषण से उनकी संरक्षा करेगा।"

छह वर्ष से चौदह वर्ष तक की आयु के सभी बालकों के लिए निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का उपबंध करने के लिए अधिनियम। निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिनियम, 2009

19. **भोजन का अधिकार**, by Prakash Louis, 2011, Xavier Institute of Social Research, Patna, pp 134+6, PB, Rs. 50/-

भोजन हर इंसान को जीवित रखने के लिए अतिआवश्यक वस्तु है। यह सर्वविदित है कि भोजन के अभाव में इंसान जी नहीं पाएगा। पर्याप्त भोजन नहीं मिलने पर कोई भी इंसान स्वस्थ जीवन व्यतीत नहीं कर पाएगा। भोजन के अभाव में लोग क्रियाशील नहीं रह पाएंगें। इस अवस्था में उन्हें कोई रोजगार नहीं देगा। वे अपने आप को संभल नहीं पाएंगे। साथी ही, वे अपने बच्चों की भी देखरेख नहीं कर पाएंगे। वे अपने बच्चों के बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर पायेंगें। भूख शारीरिक एवं मानसिक विकास में बाधक बनता है। मस्तिष्क का विकास भूख के कारण पूर्णरूपेण नहीं हो पाएगा। भूख उत्पादन शक्ति के विकास में आड़े आता है। भूख न केवल व्यक्ति को मगर समूह को भी प्रभावित करता है।

भूख कहीं भी क्यों न हो, वह विकास के विरूद्ध है।
भूख कहीं भी क्यों न हो, वह सुशासन के विरूद्ध है।
भूख कहीं भी क्यों न हो, वह शांति के विरूद्ध है।
भूख कहीं भी क्यों न हो, वह मानवता के विरूद्ध है।

20. Lokpal Bill: Ombudsman/Jan Lokpal Bill, by Prakash Louis, 2011, Xavier Institute of Social Research, Patna, pp 177+8, PB, Rs. 50/-

In early 1960s, mounting corruption in public administration set the winds blowing in favour of an Ombudsman in India too. The Administrative Reforms Commission (ARC) while recommending the constitution of Lokpal was convinced that such an institution was justified not only for removing the sense of injustice from the minds of adversely affected citizens but also necessary to instill public confidence in the efficiency of administrative machinery. Following this, the Lokpal Bill was for the first time presented during the fourth Lok Sabha in 1968, and was passed there in 1969. But it is pending in the Rajya Sabha from then onwards. Even after 40 years, the rules of India have not mustered enough political will to enact a comprehensive Lokpal legislation.

The ruling elite of India have been speaking of and engaged in economic reform. But the people of India have been demanding for educational reform, electoral reform, land reform, judicial reform, administrative reform and economic reform. All the efforts by the citizens of India and the ruling elite it is hoped would result in enacting a legislation which would address the issue of corruption. But that is not the end of the story, in the long run, every Indian would like to see an India where governance and development are pro-people and pro-poor. Only, when this is done, can India be truly a democratic, socialist and secular state.

21. **बिहार में अल्पसंख्यक समुदायों का अधिकार**, by Prakash Louis, 2014, Xavier Institute of Social Research, Patna, pp 106+14, PB, Rs. 50/-

अल्पसंख्यक समुदाय भारत में ही नहीं विश्वभर में अपने अस्तित्व, अस्मिता, अधिकार एवं इज्जत की लड़ाई में सदियों से लगा है। उभरते राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय परिवेश में अल्पसंख्यक समुदाय का संघर्ष और भी तेज, बहुआयामी एवं जटिल हो गया है। परिस्थिति का जायजा लेते हुए संयुक्त राष्ट्र ने 1992 में अंतर्राष्ट्रीय प्रावधान प्रस्तुत किया था, जिसका शीर्षक है, "Declaration on the Rights of Persons Belonging to National, Ethnic, Religious and Linguistic minorities" यानी राष्ट्रीय, नस्ल, धार्मिक एवं भाषाई अल्पसंख्यकों के अधिकार का घोषणापत्र। इस घोषणा-पत्र के द्वारा यह कोशिश की गई है कि प्रत्येक राष्ट्र की सरकार यह कोशिश करें कि राष्ट्रीय, नस्ल, धार्मिक एवं भाषाई अल्पसंख्यक सुरक्षित रहें, साथ ही सरकारें इस दिशा में उचित कानून बनाएँ।

लेकिन, धरातल से उभरता हर खबर यह बताता है कि हर जगह, हर समय, हर परिस्थिति में अल्पसंख्यक के अधिकारों का हनन होता रहता है। कभी-कभी यह सुनने को मिलता है कि अल्पसंख्यक समुदाय का हनन इसलिए होता है कि वह संख्या के आधार पर अल्पसंख्यक हैं। मगर यह पूर्ण सच्चाई नहीं है। अल्पसंख्यक समुदायों का शोषण-दमन किसी भी देश के राजनैतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक एवं आर्थिक ढाँचे की वजह से होता है। डॉक्टर भीमराम अम्बेदकर ने कहा था, "अल्पसंख्यक को संख्या के आधार पर नहीं, स्वामित्व के आधार पर आँकना चहिए।" इस सिलसिले में ऊँची जाति एवं वर्ग के लोग प्रबल होते हैं और उनका प्रभुत्व हर क्षेत्र में कायम रहता है। इस माने में दलित, आदिवासी और अल्पसंख्यक शक्तिहीन एवं वंचित हैं।

[प्रस्तावनाः प्रकाश लुईस]

22. "Policy Documents of the Government of India", by Prakash Louis, 2006, Indian Social Institute, New Delhi, pp 340+8, Price: Rs. 150/-

Policy formulation and planning are understood to have clearly and categorically delineated aims and objectives. They are to aim at utilizing more effectively and efficaciously the resources both human and material so as to ensure that all the citizens of a nation benefit out of them. When the government of any country introduce policies and plans the immediate objective is to ensure development and the long-term objective is to guarantee that the benefits of growth and development lead to equality. National planning is also envisaged to streamline the various processes that go on in the socio-economic, political and cultural realms. In the ultimate analysis, planning is aimed at preparing, presenting and promoting a national agenda which in ultimate analysis address the various issues that affect the citizens in general and the common masses in particular.

"Policy Documents of the Government: A Reader for Understanding Legislations that determine lives the Lives of Millions of Citizens" is a compendium of policies of the Government of India. This compendium contains ten policies enacted from 1998 to 2002. in this compendium an attempt is made to present a preliminary critical appraisal of these policies that affect the lives of millions of citizens of this country.

23. आम आदमी के मुद्दे, by Prakash Louis, 2006, Xavier Institute of Social Research, Patna, pp 272+6, PB, Rs. 50/-

भारतवर्ष हमेशा की तरह अब भी दो पारम्परिक प्रक्रियाओं के तहत गुजर रहा है। पहला, रह-रहकर कई सारे विडम्बनाएं एवं विषंगतियाँ सामाजिक, आर्थिक, सांस्क्रतिक एवं राजनैतिक क्षेत्र में दस्तक दे रहें। ये विषंगतियाँ एवं विडम्बनाएं विकासशील इस देश को अग्रसर होने में अवरोधक बन रहे हैं। इतना ही नहीं, नई तकनीकी और अविष्कारों के फलस्वरूप जो भी विकास देश और समाज कर पाया, उस प्रगति को ये रूकावटें सीमित कर रहे हैं। दूसरी ओर देश और समाज कई आयामों में

अभूतपूर्व विकास एवं प्रगति कर विश्व के देशों में एक महत्वपूर्ण देश के रूप में उभर कर आया है। इतना ही नहीं, पश्चिमी देशों में खलबली मचाने का दावा भी भारत अब कर सकता है।

इन प्रक्रियाओं के बीच में 'आम आदमी के मुद्दे' नामक लेखों का संग्रह को हम इसलिए किताब के शक्ल में पाठकों को पेश करना चाहते है, इस उम्मीद से कि आम आदमी के मुद्दा चर्चा का विषय बनें। न केवल चर्चा का विषय बनें, वरण संवाद के पश्चात कोई ठोस काम भी हो।

सरकार के द्वारा हाल ही में बनाया गयी दो नीतियाँ, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी नीति एवं सूचना का अधिकार नीति अपने आप में सबल नीति-निर्धारण है जो आम आदमी के मुद्दे बन सकते हैं। इस प्रकार की नीति, योजना एवं कार्यक्रमों को जनसाधारण तक पहुँचाने से आम आदमी और मुखरित हो सकते हैं।

[प्रस्तावनाः प्रकाश लुईस]

D. Seminar Publications

24. "Society and Technology: Impact, Issues and Challenges, Edited by Jaismin Kantha, Jose Kalapura and T. Nishaant, 2015, Janaki Prakashan, Patna, St. Xavier's College of Management & Technology, Patna & Xavier Institute of Social Research, Patna, pp 335+40, HB, Rs. 995/-, ISBN 978-93-84767-00-6

This book is an attempt to comprehend and analyse some of the paradoxes of the impact of technology on society through inter and multidisciplinary perspective. The relationship between human and machines has come to assume central place not only in social sciences but in all academic fields. What has happened is that technology as part of modern development tool has become unsustainable, the modern science based technologies have been posing risks to people and environment; hence the need arose to debate the issues and challenges related to technology. The contributors of this book pursue different theoretical perspectives but a focus common to all is the role of technology in society, the issues and challenges at stake, the social forces that shape technological decisions and the choices that are open to society with respect to the uses of technology. Further the book compiles issues which are current and burning like role and impact of technology on education, economy, healthcare, environment, development and social sector. It is through investigation of these issues that the book attempts to contribute to a greater understanding of discourses on the impact of technology on society.

25. "Agriculture and Development of Bihar, Edited by Jose Kalapura, 2016, Xavier Institute of Social Research, Patna, pp 86+10+12, HB, Rs. 250/-, ISBN 978-81-907860-6-5

This book has emerged from a seminar on "Agriculture and Development of Bihar: Prospects, Issues and Challenges" held on March 13, 2016, at Amhara, Bihta, Patna District. The seminar was organized by Xavier Institute of Social Research (XISR) with a view to informing and enriching the cultivators of Bihta on the best practices of agriculture with the collaboration of agriculture specialists, agri-supportive financial institutions and the concerned administrative personnel from the Department of Agriculture, Government of Bihar. The papers and reports in the following pages indicate the proceedings of the Seminar.

First, the concept note Jose Kalapura highlights the present situation of agriculture and agriculturists of Bihar; the keynote address by Dr. Jagdish Prasad places in perspective the potentialities and actual situation of agriculture in Bihar and calls for greater outlay and availability of resources to further develop agriculture, which is the mainstay of Bihar's economy; the special input article contributed by Dr. Rashmi Prasad points out how the economy and poverty in Bihar are linked to agriculture; input lecture by Dr. Anil Kumar Jha,

Joint-Secretary of the Department of Agriculture, Bihar Government, points to the great prospects of agriculture in Bihar with the help of the State's Agriculture Road Map for the coming years; the lecture by Dr. Raj Dev Singh, an accomplished agriculture specialist retired from the Indian Council of Agriculture Research (ICAR), Patna is another scholarly input with concrete guidelines for cultivators as to improve crop yields; the inputs from agri-financial experts from NABARD, Mr. Mithilesh Kumar and M. M. Ashraf and Mr. Amitabh Pandey from the State Bank of India, Patna throws much light on agri-finance programs of both the banks. The book also contains a detailed report of the seminar, besides the program, some media clippings and photos of the event.

26. **"Education of the Marginalised Communities in Bihar: Exploring Financial Inclusion"** ed Jose Kalapura, 2017, Xavier Institute of Social Research, Patna, pp xii+232.

This Proceedings book has emerged from a seminar on "Education of the Marginalised Communities in Bihar: Exploring Financial Inclusion" organized by Xavier Institute of Social Research (XISR), on March 17, 2017. This book is yet another publication of XISR, whose aim is to create forums for interaction and interface between scholars, experts, civil administrators and so on with the deprived people whose rights are to be safeguarded and development ensured. Education is the key to development in a society. Though Bihar has made high growth in primary education especially of girls during the recent past, it is far behind many developed states in India. It may be noted that Dalits constitute the vast majority of the marginalized communities in Bihar, and for that matter, in the whole country. Hence we undertook a study of the situation of education of the major Dalit communities in Bihar.

The various chapters of the book are: Section-I-Ch-1, concept note by Dr. Jose Kalapura and Dr. Ashutosh Kumar Vishal; Ch-2, the speech of the Chief Guest, Padmasri Sudha Varghese; Ch-3, summary of keynote address in Hindi by Prof. Vinay Kantha; Ch-4, the full text of the key note "Understanding Exclusion and Inclusion of the Marginalised Students"; Ch 5-Financial Inclusion by NABARD, by Mr. Sanjay Kumar; Ch 6-Dalit Education in Bihar: Situation, Aims and Methodology of Study by Jose Kalpura and Ashutosh Vishal; Ch 7-Quality of Education by Ashutosh Vishal; Ch-8-Exclusion and Discrimination by Ashutosh Vishal; Ch-9, Parents, School and Community, by Ashutosh Vishal; Ch-10, Conclusion and Suggestions by Jose Kalapura and Ashutosh Vishal. A exhaustive bibliography concludes Section I. Section II contains Seminar Report, media release, media repors, media clippings and photos.

27. हिन्दी दलित साहित्य में मानव-मुक्ति की अवधारणा, by Sushil Bilung, 2017, Xavier Institute of Social Research, Patna & Jagriti Prakashan, Patna, pp. 1-372, HB, Rs. 950/-, ISBN 978-93-82371-92-2

'हिन्दी दलित साहित्य में मानव-मुक्ति की अवधारणा' शीर्षक पुस्तक में सुशील बिलुँग ने दलित चिंतन की अवधारणा, दलित-शोषण तथा पीड़न के परंपरागत कारण, दलित साहित्य में दलित मुक्ति की क्रांतिकारी पहल तथा मानवीय शोषण तथा विषमता के विविध पक्षों के सबल विरोध पर गहराई से विचार किया है।

दलित साहित्य दलित समाज को प्रतिबिंबित करता है। यह साहित्य न केवल दलितों की वेदना, पीड़ा, आक्रोश, चीख, उत्पीड़न, शोषण, अत्याचार, जिजिविषा एवं दयनीय घीसी-पिटी जिंदगी की कहानियों का साहित्य है वरन् दलितों, पिछड़ों, शोषितों की सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनैतिक, आर्थिक, धार्मिक एवं वैचारिक क्रांति का साहित्य भी है। यह हिन्दुवाद, ब्राह्मणवाद, सामंतवाद एवं पूंजीवाद के विरूद्ध क्रांति के उद्घोष का दस्तावेज है। इसका दार्शनिक आधार महात्मा ज्योतिबा फुले-अंबेदकरवाद, महात्मा बुद्ध और मार्क्स का दर्शन है। इन्हीं महापुरूषों के दर्शन से अलंकृत साहित्य ही सही मायने में दलित साहित्य है।

दलित साहित्य में सामाजिक व्यवस्था का विद्रोह हो, अथवा ब्राह्मण धर्म के विरूद्ध आवाज अथवा सामंती प्रथा का विद्रोह हो, या राजनीतिक नेताओं के विरूद्ध व्यंग्यात्मक आवाज या असहाय स्थिति में ईश्वर की चुप्पी पर प्रश्न अथवा दलित नेताओं का चित्रण ही क्यों न हो, एक ही केन्द्रिय भाव को उजागर करते हैं और वह है- एक क्रांति के आह्वाहन का, एक नये समाज के निर्माण का, एक नव इंसानियत को गढ़ने का, एक सच्चे मनुष्य की परिभाषा को ढूंढ़ने का। यह सच्चे अर्थ में एक मानवीय समाज की स्थापना का साहित्य है।

दलित साहित्य की लंबी परंपरा है किन्तु साहित्य को इस अभिधान के साथ विवेचन विश्लेषण की परंपरा नई है या आधुनिक है। प्राचीन काल में जो रचनाकार बड़ा होता था वह अपने व्यक्तिगत या सीमित समाज के दुख-दर्द की बातें कम और वृहत्तर मानवीय समाज की संवेदना को अधिक निरूपित करता था।

सुशील बिलुँग की मान्यता तथा सोचना है कि मुक्ति के लिए शिक्षा एवं ज्ञान आवश्यक है। शिक्षा से योग्यता विकसित होगी, योग्यता से राजनीति, शासन-प्रशासन में उचच पद मिलेगा। विद्वान तथा शक्ति संपन्न का आदर हर स्थान पर होता है। हर जीव ईश्वर की ही जाति का है, क्योंकि वह ईश्वर का ही अंश है, उसमें अनंत संभावनाएँ हैं, अपने तप, बल, ज्ञान तथा साधना से वह मनुष्य से ईश्वर बनने का सामर्थ्य रखता है। भारत जिसकी विश्व में इतनी गरिमा, महिमा रही है उसमें यहाँ के मूलवासियों का कम योगदान नहीं रहा है। 'दलित कहलाने के बजाय मूलवासी कहलाएँ तो कहीं ज्यादा अस्मिता के बोध में मजबूती आएगी।' सुशील का कथन है कि 'नकारात्मक मानसिकता से ग्रस्त दलित समाज को सकारात्मक मानसिकता उपजानी होगी।'

निश्चित रूप से सुशील बिलुँग ने अपनी कृति में दलित साहित्य के विषय में नई सोच की स्थापना की है। उन्होंने विमर्श को नई दिशा दी है। उनका यह कार्य मानव मुक्ति के लिए मील का पत्थर होगा।

(प्रो० रामकिशोर शर्मा, आचार्य, हिन्दी विभाग, केन्द्रीय विश्वविद्यालय, इलाहाबाद)

29. Bihar ka Paryavaran: Dasha aur Disha (Environment in Bihar: Situation and Direction) by Jose Kalapura & Niraj Kumar, 2017, Janaki Prakashan & Xavier Institute of Social Research, Patna, pp. 217+x, PB ISBN 978-93-84767-88-4. Rs. 250/ HB ISBN 978-93-84767-88-4; Rs. 650/-

पर्यावरण संकट दुनियाभर का एक महत्वपूर्ण मुद्दा बन गया है। इस मुद्दे पर अधिकांश राष्ट्रों ने चिंता व्यक्त की है। संकट का समाधान निकालने के लिए अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर नीतियाँ बनाई जा रही हैं। लोगों में धीरे-धीरे पयावरण संकट के प्रति जागरूकता भी आ रही है और उसके समाधान के उपाय किये जा रहे हैं। स्थानीय स्तर पर भी पर्यावरण संकट दिनोंदिन गहराता जा रहा है लेकिन इसके प्रति जागरूकता का अभाव है। इस दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल करते हुए जेवियर इंस्टीच्यूट ऑफ सोशल रिसर्च ने स्थानीय मुद्दे को ध्यान में रखते हुए राज्य के पर्यावरण संकट एवं उसके समाधान के उपाय पर आधारित एक पुस्तक प्रकाशित किया है। वैसे तो राष्ट्रीय स्तर पर पर्यावरण को लेकर कई पुस्तकें प्रकाशित की गई है लेकिन बिहार के पर्यावरण पर आधारित संभवतः यह पहली पुस्तक है जिसमें प्रदेश के प्राकृतिक धरोहरों पर विस्तार से प्रकाश डाला गया है। यह पुस्तक पूर्ण रूप से बिहार के भौगोलिक वातावरण पर आधारित है। पुस्तक में राज्य की नदियों, तालाबों, ताल, आहर, पईन, पोखर, पहाड़ों और जंगलों की चर्चा की गई है। राज्य में लुप्त हो रही पौधों एवं फसलों की प्रजातियाँ, संकटग्रस्त पशुओं के ब्रीड आदिको भी प्रमुखता से उठाया गया है। उम्मीद है कि इस पुस्तक से राज्य के पर्यावरण संकट के बारे में राज्य के लोगों में सामाजिक चेतना पैदा करने में काफी मदद मिलेगी। खासकर स्कूलों एवं

कॉलेजों में पढ़ने वाले छात्रों को इस पुस्तक से काफी लाभ मिलने की आशा है। (डॉ० बिहारी सिंहए विभागाध्यक्ष, स्नातकोत्तर पर्यावरण विज्ञान विभाग, ए० एन० कॉलेज, पटना)